

भारत का कौशल विकास परदृश्य

यह एडिटरियल 23/07/2024 को 'लाइवमटि' में प्रकाशित "How skilling initiatives will drive economy, bridge gender gap" लेख पर आधारित है। इसमें वर्ष 2047 तक 'वकिसति भारत' बनने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भारत की बेरोज़गारी-रोज़गार के अंतराल को दूर करने की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसके लिये शिक्षा, रोज़गार और कौशल पहलों में पर्याप्त नविश की आवश्यकता है जिस पर केंद्रीय बजट 2024-25 में भी बल दिया गया है।

प्रलमिस के लिये:

[सकलि इंडिया मशिन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प योजना, तेजस सकलिंग प्रोजेक्ट, इंडिया सकलिस रिपोर्ट 2024, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण \(PLFS\) 2022-23, गगि इकॉनमी, इंडिया AI मशिन, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, 3D प्रटिंग।](#)

मेन्स के लिये:

उभरते क्षेत्र जहाँ भारत कौशल प्रयासों को प्राथमिकता दे सकता है, भारत के कौशल प्रयासों से संबंधित प्रमुख मुद्दे।

भारत अपनी आर्थिक यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ विकास की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं, लेकिन उसे बेरोज़गारी-रोज़गार के बीच के अंतराल को दूर करने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वर्ष 2047 तक 'वकिसति भारत' बनने का भारत का स्वप्न तेज़ी से वकिसति हो रहे रोज़गार बाज़ार की मांगों को पूरा करने के लिये अपने युवाओं को प्रभावी ढंग से कौशल प्रदान करने पर टिका है। हाल ही में पेश किये गए केंद्रीय बजट 2024-25 ने इस प्राथमिकता को उजागर किया है, जहाँ शिक्षा, रोज़गार और कौशल पहलों के लिये पर्याप्त धन आवंटित किया गया है। हालाँकि, आगे अभी गंभीर चुनौती मौजूद है, जहाँ 15-59 आयु वर्ग के लगभग 73% कामगारों के पास कोई औपचारिक या अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं है।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। इसमें संस्थागत समर्थन को सुदृढ़ करना, उद्योग-अकादमिक जगत के संबंधों को मज़बूत करना और 'इम्पैक्ट बॉण्ड' जैसे अभिनव वित्तपोषण समाधानों का लाभ उठाना शामिल है। जब भारत इस महत्त्वपूर्ण चरण से गुज़र रहा है, उसके कौशल विकास प्रयासों की सफलता देश के भविष्य को आकार देने और इसकी आर्थिक क्षमता को साकार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कौशल विकास प्रयासों के लिये भारत को कनि उभरते क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिये?

- **नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकियाँ:** नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के सतत विकास एजेंडे में सबसे आगे है, जो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य से प्रेरित है।
 - इसमें 3.5 मिलियन से अधिक रोज़गार अवसर सृजित करने की क्षमता है, जिसके लिये सौर, पवन और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों में कुशल कार्यबल की आवश्यकता होगी।
- **AI और मशीन लर्निंग:** भारत का AI बाज़ार, जिसके वर्ष 2025 तक 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, उद्योगों को नया स्वरूप दे रहा है और कार्य के नए प्रतिमान गढ़ रहा है।
 - इस डिजिटल रूपांतरण के लिये डेटा एनालिटिक्स, एल्गोरिथम डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग में नपुण कार्यबल की आवश्यकता है।
 - **इंडिया AI मशिन (IndiaAI Mission)** एक सराहनीय शुरुआत है, लेकिन AI की गतिशील प्रकृति निरंतर 'अपस्कलिंग' एवं 'रीस्कलिंग' की मांग रखती है।
- **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और स्मार्ट सटीज़:** IoT और स्मार्ट सटीज़ पहल का अभिसरण भारत को अधिक 'कनेक्टेड' एवं कुशल भविष्य की ओर ले जा रहा है।
 - **IoT बाज़ार के 9.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने और 100 स्मार्ट सटीज़ की योजना के साथ, IoT प्रोग्रामिंग, डेटा सुरक्षा और एकीकृत शहरी नियोजन में कौशल की मांग तेज़ी से बढ़ रही है।**
 - **स्मार्ट सटीज़ मशिन** ने इस वृद्धि को गति प्रदान की है, लेकिन बहुवर्षिक कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रबल आवश्यकता महसूस की जा रही है।
- **इलेक्ट्रिक वाहन और सतत गतिशीलता:** भारत का वर्ष 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य ऑटोमोटिव क्षेत्र में

क्रांति लाएगा, जिससे संभावित रूप से 10 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे।

◦ इस संक्रमण के लिये बैटरी प्रौद्योगिकी, चार्जिंग अवसंरचना और स्वायत्त प्रणालियों में विशेषज्ञ कार्यबल की आवश्यकता है।

- **जैव प्रौद्योगिकी और औषधि विज्ञान:** भारत का जैव प्रौद्योगिकी उद्योग—जिसके वर्ष 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, एक बड़ी सफलता के मुहाने पर खड़ा है।
 - कोविड-19 महामारी ने जीनोमिक्स, बायो-इंफॉर्मेटिक्स और वैक्सीन विकास में कुशल कार्यबल की प्रबल आवश्यकता को रेखांकित किया है।
 - यद्यपि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग भागीदारों के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम शुरू किये हैं, फरि भी इस क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है।
- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह संचार:** भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो वर्ष 2025 तक 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकती है, नज़ी खलाइयों के लिये इस क्षेत्र को खोलने के साथ एक नए युग में प्रवेश कर रही है।
 - इस वसतिार से उपग्रह डज़ाइन, अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन और पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष परिसंपत्तियों में कौशल की मांग पैदा होगी।
- **साइबर सुरक्षा:** जहाँ भारत को वर्ष 2022 की पहली तमिही में ही 18 मिलियन से अधिक साइबर हमलों का सामना करना पड़ा, साइबर सुरक्षा के महत्त्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
 - इस परिदृश्य में भारत को एथिकल हैकगि, नेटवर्क सुरक्षा और साइबर फोरेंसिक में कुशल पेशेवरों की तत्काल आवश्यकता है।
- **3D प्रटिगि और एडटिवि मैन्युफैक्चरगि:** भारत के 3D प्रटिगि बाज़ार के वर्ष 2023 से 2030 तक 20.3% की उच्च CAGR से बढ़ने का अनुमान है।
 - यह विभिन्न उद्योगों में विनिरिमाण प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यह उभरता हुआ क्षेत्रकंप्यूटर-एडेड डज़ाइन (CAD) मॉडलगि, सामग्री विज्ञान और एडटिवि मैन्युफैक्चरगि के लिये गुणवत्ता नियंत्रण में विशेषज्ञता की मांग रखता है।
- **क्वांटम कंप्यूटगि:** क्वांटम प्रौद्योगिकियों के प्रति भारत की प्रतिबिद्धता (जिसकी पुष्टि 'क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मशिन' के लिये 8,000 करोड़ रुपए के आवंटन से होती है) इस अत्याधुनिक क्षेत्र में गंभीरता से आगे बढ़ने का संकेत देती है।
 - यह क्षेत्र क्वांटम एल्गोरदिम, क्रिप्टोग्राफी और एरर करेक्शन में अत्यधिक विशिष्ट कौशल की मांग रखता है।

कौशल विकास से संबंधित सरकार की प्रमुख पहलें:

- [सकलि इंडिया मशिन](#)
 - [प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना](#)
- [संकल्प योजना](#)
- [तेजस सकलिगि प्रोजेक्ट](#)
- इसके अलावा, मॉडल कौशल ऋण योजना (Model Skill Loan Scheme) को संशोधित किया जाएगा ताकि सरकार समर्थति गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा दी जा सके, जिससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को लाभ मल्लिगा। (केंद्रीय बजट 2024-25)

भारत के कौशल प्रशिक्षण संबंधी प्रयास बेहतर रोजगार परिणामों में क्यों नहीं परिवर्तित हो रहे?

- **संरचनात्मक आर्थिक बाधाएँ:** भारत की अर्थव्यवस्था एक बड़े अनौपचारिक क्षेत्र (लगभग 85-90%) और [सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों \(MSMEs\)](#) की प्रधानता से चिह्नित होती है।
 - कई MSMEs के पास औपचारिक कौशल प्रशिक्षण में निवेश करने के लिये संसाधनों या प्रोत्साहनों की कमी होती है। इसका परिणाम है कि युवा कार्यबल का केवल 4.4% ही औपचारिक रूप से कुशल है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार)। MSMEs प्रायः कार्य करते हुए सीखने (on-the-job learning) को प्राथमिकता देते हैं।
 - अधिकांश रोजगार की अनौपचारिक प्रकृति का अर्थ यह भी है कि औपचारिक प्रमाणपत्र प्रायः वेतन प्रीमियम या नौकरी की सुरक्षा के रूप में व्यक्त नहीं होते, जिससे कौशल विकास कार्यक्रमों का कथित महत्त्व कम हो जाता है।
- **जनसांख्यिकीय और भौगोलिक असमानताएँ:** [इंडिया सकलिस रिपोर्ट 2024](#) से उजागर हुआ है कि विभिन्न राज्यों में रोजगार योग्यता (employability) में व्यापक भिन्नता है।
 - शहरी केंद्र उच्च तकनीकी कौशल की मांग रखते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बुनियादी और पारंपरिक कौशल की आवश्यकता होती है।
 - मौजूदा कौशल प्रशिक्षण मॉडल्स में इस असमानता को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है। इसके अलावा, आंतरिक प्रवासन पैटर्न कौशल मानचित्रण और वितरण को जटिल बनाते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र में अर्जित कौशल दूसरे क्षेत्र में प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकीय व्यवधान और कौशल अप्रचलन:** प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की तीव्र गति, विशेष रूप से AI, मशीन लर्निगि और स्वचालन जैसे क्षेत्रों में, विभिन्न पारंपरिक कौशलों को शिक्षा प्रणाली के अनुकूल होने से पहले ही अप्रचलित बना रही है।
 - [वशिव आर्थिक मंच \(WEF\)](#) की वर्ष 2020 की 'फ्यूचर ऑफ़ जॉब्स रिपोर्ट' के अनुसार, बढ़ते प्रौद्योगिकी अंगीकरण के कारण वर्ष 2025 तक सभी कार्यक्रमों में से आधे को पुनः प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी।
 - इससे कौशल विकास में लगातार एक 'कैच-अप गेम' की स्थिति उत्पन्न होती है। चुनौती केवल नए कौशल सिखाने की नहीं है, बल्कि निरंतर सीखने और अनुकूलनशीलता की मानसिकता पैदा करने की है, जसि वर्तमान कार्यक्रम संबोधित करने में प्रायः विफल रहते हैं।
- **उच्च शिक्षा प्रणाली के साथ असंगति:** उच्च शिक्षा प्रणाली और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच एक गंभीर असंगति पाई जाती है।
 - [आवधिक शरम बल सर्वेक्षण \(PLFS\) 2022-23](#) के अनुसार, 15-29 आयु वर्ग के केवल 4.4% युवाओं को औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।
 - शैक्षणिक डिग्रियों और व्यावसायिक योग्यताओं के बीच एकीकरण का अभाव एक वरिधाभास पैदा करता है, जो कौशल-आधारित शिक्षा का अवमूल्यन करता है।

- **उभरती हुई गति अर्थव्यवस्था** पर अपर्याप्त ध्यान: गति अर्थव्यवस्था और प्लेटफॉर्म-आधारित कार्य (जो 90 मिलियन नौकरियों की क्षमता रखता है) का उदय रोज़गार की प्रकृति को बदल रहा है, जहाँ **स्व-प्रबंधन, डिजिटल साक्षरता और उद्यमशीलता** सहित विभिन्न प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है।
 - वर्तमान **कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी भी काफी हद तक पारंपरिक रोज़गार मॉडल** की ओर उन्मुख हैं और इस नए परतमिन के लिये कामगारों को पर्याप्त रूप से तैयार करने में विफल हैं।
- **मूल्यांकन मॉडल की सीमाएँ:** कौशल विकास के लिये वर्तमान वित्तपोषण मॉडल प्रायः दीर्घकालिक परणामों (सतत, रोज़गार, करियर में प्रगति) की तुलना में **अल्पकालिक** आउटपुट (प्रशिक्षित लोगों की संख्या) को प्राथमिकता देते हैं।
 - **आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23** से पता चला है कि PMKVY 2.0 के तहत **1.1 करोड़** लोगों को प्रशिक्षित किया गया, लेकिन इनमें से केवल 21.4 लाख को ही नौकरी मिली।
 - इससे विकृत प्रोत्साहन पैदा होते हैं जो प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रासंगिकता से समझौता करते हैं।
- **पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) से संबंध चुनौतियाँ:** यद्यपि RPL को अनौपचारिक कौशल को मान्यता देने के लिये शुरू किया गया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं।
 - मूल्यांकन प्रक्रियाएँ प्रायः इतनी परिष्कृत नहीं होतीं कि अनौपचारिक माध्यमों से अर्जित कौशलों को सटीक रूप से देख सकें और प्रमाणित कर सकें, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा कौशलों का कम मूल्यांकन हो पाता है।

भारत के कौशल प्रयासों के पुनरुद्धार के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- **मांग-संचालित कौशल मानचित्रण और पूर्वानुमान:** एक सुदृढ़, रियल-टाइम श्रम बाज़ार सूचना प्रणाली लागू की जाए जो कौशल मांगों का पूर्वानुमान लगाने के लिये बगि डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करे। इस प्रणाली की नमिनलखित भूमिकाएँ होंगी:
 - वसित्त, कषेत्र-वशिषिट डेटा एकत्र करने के लिये उद्योग संघों के साथ सहयोग करना।
 - जॉब पोस्टिंग, उद्योग रपिर्ट और आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण करने के लिये AI एल्गोरिदम का उपयोग करना।
 - राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर तमिाही कौशल मांग पूर्वानुमान तैयार करना।
 - **सगिापुर की स्कलिस्फ्यूचर (SkillsFuture) पहल** राष्ट्रीय कौशल रणनीति को निर्देशित करने के लिये ऐसी ही एक प्रणाली का उपयोग करती है और यह भारत के लिये एक आदर्श मॉडल हो सकती है।
- **मॉड्यूलर और स्टैकेबल कौशल प्रमाणन (Modular and Stackable Skill Certifications):** मॉड्यूलर, स्टैकेबल प्रमाणन की एक प्रणाली शुरू की जाए जो शक्तिषार्थियों को क्रमिक रूप से कौशल विकास की अनुमति दे:
 - जटलि कौशल समूहों को छोटे, प्रमाणन-योग्य मॉड्यूलों में विभाजित किया जाए।
 - शक्तिषार्थियों को समय के साथ क्रेडिट जमा करने की अनुमति दी जाए, जिससे उच्च योग्यता प्राप्त हो। सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक मॉड्यूल का तात्कालिक बाज़ार मूल्य हो।
 - यह दृष्टिकोण कौशल अर्जन को अधिक लचीला और सुलभ बनाकर भागीदारी को बढ़ा सकता है।
- **मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण:** माध्यमिक स्तर से ही **स्कूली पाठ्यक्रम में व्यावसायिक पाठ्यक्रम (vocational courses)** को शामिल किया जाए:
 - **आठवीं कक्षा** से व्यावसायिक विषयों को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाए।
 - व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच **क्रेडिट स्थानांतरण प्रणाली** विकसित की जाए।
 - सुनिश्चित किया जाए कि वोकेशनल शिक्षकों के पास उद्योग अनुभव और शैक्षणिक प्रशिक्षण दोनों हों।
 - जर्मनी की दोहरी शिक्षा प्रणाली, जो प्रशिक्षुता को व्यावसायिक स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ती है, एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकती है।
- **उद्योग-आधारित उत्कृष्टता कौशल केंद्र:** अग्रणी कंपनियों के साथ साझेदारी में कषेत्र-वशिषिट **उत्कृष्टता कौशल केंद्र (Skill Centers of Excellence)** स्थापित किये जाएँ:
 - इन केंद्रों को सरकारी सहायता से उद्योग संघों द्वारा संचालित किया जाना चाहिये।
 - उन्हें उभरते कषेत्रों में **हाई-एंड एवं फ्यूचर-रेडी कौशल** पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
- **गति अर्थव्यवस्था पूर्व-तैयारी या तत्परता पहल (Gig Economy Preparedness Initiative):** गति अर्थव्यवस्था के लिये कामगारों को तैयार करने हेतु एक समर्पित कार्यक्रम शुरू किया जाए:
 - डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्व-प्रबंधन और वित्तीय साक्षरता पर पाठ्यक्रम विकसित किया जाए।
 - **गति वर्कर्स** की सामाजिक सुरक्षा को औपचारिक बनाने और बढ़ावा देने के लिये गति वर्कर रजिस्ट्री का निर्माण किया जाए।
 - प्रासंगिक कौशल मॉड्यूलों की सह-अभिकल्पना (co-design) के लिये प्लेटफॉर्म कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित की जाए।
- **प्रशिक्षुता मॉडल में सुधार:** प्रशिक्षुता प्रणाली में सुधार कर इसे नियोक्ताओं और प्रशिक्षुओं दोनों के लिये अधिक आकर्षक बनाया जाए:
 - प्रशिक्षुता की संख्या और गुणवत्ता के आधार पर कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।
- **हरति कौशल एकीकरण कार्यक्रम:** सभी प्रासंगिक कौशल विकास कार्यक्रमों में हरति कौशल को एकीकृत किया जाए:
 - प्रत्येक कषेत्र-वशिषिट पाठ्यक्रम के लिये **'हरति कौशल' ऐड-ऑन मॉड्यूल विकसित** किया जाए।
 - उभरते हरति रोज़गारों अवसरों (जैसे सौर पैनल तकनीशियन, अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञ) के लिये विशेष पाठ्यक्रम बनाए जाएँ।
 - पाठ्यक्रम विकास और इंटरनशिप के लिये पर्यावरण संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करें।
- **कौशल संवर्द्धन के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता (Rural Entrepreneurship through Skill Enhancement- RESE):** सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) को डिजिटल सेवा कौशल केंद्रों में परिणत किया जाए।
 - ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के लिये प्रासंगिक पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
 - मार्गदर्शन, सूक्ष्म वित्तपोषण और बाज़ार संपर्क सहायता प्रदान की जाए।
- **प्रशिक्षक प्रशिक्षण उत्कृष्टता कार्यक्रम:** उच्च गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षकों को विकसित करने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम स्थापित किया जाए:

- सभी प्रशिक्षकों के लिये अनिवार्य उद्योग इंटरनशिप।
- प्रशिक्षकों को उद्योग के रुझानों के साथ अद्यतन रखने के लिये नियमिति पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
- प्रशिक्षकों के लिये छात्र परणामों से जुड़े प्रदर्शन-आधारति प्रोत्साहन।
- **कौशल वकिस को मनरेगा (MGNREGA) के साथ एकीकृत करना:** कौशल वकिस घटकों को शामिल करते हुए मनरेगा को बेहतर बनाया जाए
 - 100 दिन की गारंटीशुदा रोजगार योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की जाए।
 - ग्रामीण वकिस और स्थानीय उद्योगों से संबंधति कौशल पर ध्यान केंद्रति कथिा जाए।
 - इस कार्यक्रम के माध्यम से नए कौशल हासल करने के लयि अतरिकित प्रोत्साहन प्रदान कथिा जाए।

अभ्यास प्रश्न: वचिर कीजथि कभिरत के कौशल वकिस प्रयास बेहतर रोजगार परणामों में परणित क्यों नहीं हो रहे हैं और इस अंतराल को दूर करने के उपाय सुझाइये।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. प्रधानमंत्री कौशल वकिस योजना के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजथि: (2018)

1. यह श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रमुख योजना है।
2. यह अन्य बातों के अलावा सॉफ्ट स्कलिस, उद्यमति, वत्तितीय और डजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
3. इसका उद्देश्य देश के अनयमति कार्यबल की दक्षताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे के अनुरूप बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. "भारत में जनांकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कभिरारी जनशक्ति अधिक शक्ति, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती।" सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोजगार-योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लयि कौन-से उपाय कथिे हैं? (2016)